केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों पर ऋण-भार

2277. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1994 तक केन्द्रीय सरकार और सभी राज्य सरकारों पर कुल कितना ऋण देय है;

(ख) सकल राष्ट्रीय आय में ऋण भार की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों से सकल राष्ट्रीय आय की प्रतिशतता के रूप में कुल ऋण-भार में निरन्तर वृद्धि होती रही है;

(घ) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऋण भार को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल): (क) एवं (ख) वर्षांत में ही स्थिति दी जा सकती है, न कि वर्ष के मध्य में। 1994-95 (संशोधित अनुमान) के अंत में सरकारी खाते (बही मूल्य पर) में विदेशी ऋण को मिलाकर भारत सरकार के कुल बकाया सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं 541329 करोड़ रुपये थी और यह सकल घरेलू उत्पाद का 59.6% होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन (1994-95) के अनुसार 1994-95 (संशोधित अनुमान) के अंत में राज्य की कुल बकाया देयताएं 1,84,020 करोड़ रुपए थीं जिसमें से 1,17,241 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार द्वारा ऋण दिया गया था।

(ग) एवं (घ) 1992-93 के आगे सभी स्रोतों से केन्द्र सरकार का निवल उधार (राजकोषीय घाटा संबंधित वर्ष के सकल-घरेलू उत्पाद के प्रश्न सहित नीचे तालिका में दिया गया है।

वर्ष	कुल उधार (निवल) (करोड़ रुपए)	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में
1992-93	40173	5.7
1993-94	60257	7.7
1994-95 (संशोधित अनुमान)	61035	6.7
1995-96 (बजट अनुमान)	57654	5.5

(ङ) कर राजस्व तथा अन्य ऋण-भिन्न प्राप्तियों को अधिकतम करने को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि उधार लिए गए ऋण पर निर्भरता कम की जा सके। स्थिति का ध्यानपूर्वक अनुवीक्षण किया जाता है।

बैंकों में जमा और ऋण का अनुपात

2278. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार राज्य स्थित बैंकों में जमा और ऋण का अनुपात क्या है;

(ख) देश के अन्य राज्यों में स्थित बैंकों में जमा और ऋण के अनुपात का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंकों द्वारा दिया गया प्रति व्यक्ति ऋण का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में इस ऋण की धनराशि सबसे कम है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार, बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में जमा-ऋण संतुलन बनाये रखने के लिये क्या उपाय करने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबी प्रसाद पाल): (क) और (ख) मार्च 1993, 1994 और 1995 को समाप्त वर्ष के लिए बिहार के ऋण-जमा अनुपात सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राज्य-वार ऋण जमा अनुपात संलग्न विवरण-I में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) प्रति व्यक्ति ऋणों और जमाराशियों तथा ऋण का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण (नीचे देखिए) और अनुपत्र में दिया गया है। (देखिए परिशिष्ट 175, अनुपत्र संख्या 53)

(ङ) राज्य में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए अर्थोपायों के सुझाव देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने कृतिक बल का गठन किया है। सिफारिशों का ब्यौरा आगे विवरण-III में दिया गया है।